जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 322 प्रभात चूरू, शनिवार 22 मार्च, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सोनिया गांधी ने प्रणब बाबू की पहली राय मानी, अब राहुल दूसरी राय पर चलना चाहते हैं

2004 में प्रणब बाबू को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, कांग्रेस के सामने वे विकल्प प्रस्तुत करने की, जो कांग्रेस अपनी भविष्य की रणनीति के रूप में अपनाये

- पहला विकल्प, जो शॉर्टकट भी था, में सुझाया गया था कि कांग्रेस गठबंधन करे, अन्य पार्टियों के साथ और सत्ता में आये।
- दूसरा विकल्प, जो सुझाया गया था, के अनुसार, कांग्रेस स्वयं संघर्ष करे, अकेले पार्टी के संगठन को जमीन से खड़ा करे और फिर अपने दम पर सत्ता में आये।
- सोनिया गांधी ने पहला विकल्प चुना था, 2004 में पार्टी ने सरकार बनाई तथा यूपीए का जन्म हुआ था।
- अब 2025 में राहुल दूसरे विकल्प को अपनाना चाहते हैं।
- नई नीति के तहत, दिल्ली में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और अकेले ही चुनाव लड़ा और अब बंगाल में भी कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है, ममता बनर्जी का आंचल छोड़कर। इसी प्रकार लालू यादव के नज़दीक माने जाने वाले प्रदेशाध्यक्ष, अखिलेश सिंह को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तथा कन्हैया को नेता के रूप में प्रोजैक्ट किया जा रहा है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। सन् 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई उसके पहले प्रणब मुखर्जी ने कई पेपर लिखे थे जिनमें उन्होंने कांग्रेस के लिए दो विकल्प बनाए थे।

एक ''शॉर्ट कट'' विकल्प यह था, कि पार्टी गठबंधन करके सत्ता में आए। दूसरा दीर्घकालीन विकल्प था कि कांग्रेस अकेले लड़े, अपने संगठन और जनता के बीच अपने आधार का पुनर्निर्माण करे और फिर सत्ता में आए।

सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शॉर्ट कट को चुना और कई गठबंधनों के साथ 2004 में कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र में सरकार का नेतृत्व किया और इस तरह यू.पी.ए. का जन्म हुआ।

अब, सन् 2025 में उनके पुत्र राहुल गाँधी ने घड़ी को पीछे घुमाने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जाएं कि पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

इन्दिरा गाँधी के समय से पहले जाते हुए उन्होंने घोषणा की है कि जिला अध्यक्षों को सशक्त बनाया जाएगा, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और संसद तथा विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा, इस निर्णय में भी उनकी भूमिका होगी।

इस महीने के अंत में पार्टी के जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है।

उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों की एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती परीक्षा 2021, एक और ट्रेनी एसआई गिरफ्तार

जयपुर, 21 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एक और ट्रेनी एसआई को करौली से गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ट्रेनी एसआई रामखिलाडी मीणा से पूछताछ कर रही हैं।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा ने बताया कि एसओजी ने उप-निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के सम्बन्ध में दर्ज मामले में रामखिलाडी मीणा पुत्र तेजराम मीणा निवासी गांव ओलवाडा सवाई माधोपुर हाल प्रशिक्षु एसआई रिजर्व पुलिस लाइन करौली को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है।

- एसओजी ने सवाई माधोपुर के राम खिलाड़ी मीणा को कटौली रिज़र्व पुलिस लाइन से गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसकी जगह ''डमी'' अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी।

रामखिलाडी मीणा ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आर.एस.एस., दक्षिण भारत के राज्यों के पक्ष में खड़ा हुआ

संघ के महासचिव सी.आर. मुकुन्द ने बैंगलोर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए, मातृभाषा व कैरियर भाषा का जिक्र किया

- उन्होंने, मातृभाषा के उपयोग का समर्थन किया और यह भी कहा कि कैरियर भाषा इंगलिश या कोई और भाषा भी हो सकती है।
- संघ के महासचिव ने यह भी कहा कि डीलिमिटेशन में साउथ के प्रांतों का अनुपात बरकरार रखना चाहिये।
- पर, भाषा व डीलिमिटेशन के मुद्दे पर, देश की अखंडता को चुनौती देना, राजनीति से प्रेरित है। देश के लिये अच्छा नहीं है कि नागरिक ऐसे मुद्दों पर लड़ें।
- यह पहली बार नहीं है कि संघ ने साउथ के राज्यों को समर्थन दिया है। जुलाई में संघ के मुख पत्र, ऑर्गनाइज़र ने संपादकीय में कहा था कि ''क्षेत्रीय असंतुलन भी एक मुद्दा है, जो ''डीलिटिमेशन'' को प्रभावित करेगा। 2018 में अखिल भारतीय भाषाओं को संरक्षण व प्रोत्साहित करने की जरूरत है तथा प्राइमरी शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और डी.एम.के. (द्रमुक) के शासन वाले तमिलनाडु राज्य के बीच ''डीलिमिटेशन'' और तीन भाषा फॉर्मूला को लेकर चल रहे विवाद के बीच आर.एस.एस. ने कहा है कि ''डीलिमिटेशन'' कवायद के बाद यदि संसद में सीटों की संख्या बढ़ती है तो दक्षिणी राज्यों का शेयर बरकरार रहना चाहिए। संयोगवश, यह वही चीज है, जो द्रमुक ने इस महीने के शुरु में उठाई थी।

इस समय बैंगलुरु में चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग से इतर, एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करते हुये, आर.एस.एस. के संयुक्त महासचिव सी.आर. मुकुन्द ने लोगों द्वारा मातृभाषा के उपयोग की वकालत की। उन्होंने कहा कि कैरियर-भाषा के रूप में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा उपयोग में ली जा सकती है। लेकिन आर.एस.एस. नेता ने ''परिसीमन या भाषाओं के मुद्दे पर, उत्तर-दक्षिण के विभाजन का मुद्दा उठाकर, राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने की कोशिशों'' का विरोध किया। उन्होंने कहा, ''रूपये के प्रतीक को स्थानीय भाषा में रखे जाने की माँग, जैसे मुद्दे राजनीति-प्रेरित हैं। ऐसी चीजों पर सामाजिक नेताओं और ग्रुपों का विचार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारे खिलाफ ''हनी ट्रैप'' का भारी जाल बिछाया गया है'

- कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने अजीबोगरीब शिकायत की। और, सरकार ने इस आरोप पर गंभीरता से व गहराई से जांच कराने के आदेश दिये।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। कर्नाटक में विभिन्न राजनैतिक दलों के कम से कम 48 राजनेता ''हनी ट्रैपिंग'' प्रयासों के शिकार बन चुके हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी गहन जाँच सरकार को करनी चाहिए तथा अपराधियों को सजा देनी चाहिये। अगर राज्य के सहकारिता मंत्री रंजन के शब्दों का विश्वास किया जाये तो हनी ट्रैपिंग साफ तौर पर एक राजनैतिक हथियार का रूप ले चुका है।

उन्होंने यह आरोप कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को लगाया तथा राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध किया कि इस प्रकार की घटनाओं की तह तक पहुँचने के लिए विस्तृत जाँच के आदेश दिये जायें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी हनी ट्रैप की कोशिश के शिकार हैं।

और जब एक और मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, ने गुरुवार को हनी ट्रैप की घटनाओं को उजागर किया, तो इस मुद्दे से सदन हिल गया तथा भारी राजनैतिक हंगामा खड़ा हो गया तथा विपक्षी भाजपा ने इसकी न्यायिक जाँच की मांग की।

इस मुद्दे ने शुक्रवार तक विधानसभा में पूरी तरह तथा बड़े रूप में राजनैतिक विवाद का रूप ले लिया। भाजपा ने न्यायिक जाँच कराने तथा विधानसभा में कोई भी काम न होने देने की माँग की। हंगामे और उद्दण्ड व्यवहार के लिए 18 विधायक निलम्बित कर दिये गये। दरअसल, उन्होंने नारेबाजी की, विधानसभा अध्यक्ष यूडी खेदर तथा मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया पर कागज़ात और किताबें फैंकी तथा वैल में आ गए।

जब विधायकों ने, सदन की गरिमा बनाये रखने की स्पीकर की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा सदन की कार्यवाही में विघ्न डालते रहे, तो स्पीकर ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे विधायकों में से 18 विधायकों को छः महीने के लिये निलम्बित कर दिया। अब, इस निलम्बन को लेकर विधानसभा के बाहर तीव्र बहस शुरु हो गई है।

जैसी कि अपेक्षा थी, कांग्रेस ने स्पीकर की कार्यवाही को उचित ठहराया है, जबकि भाजपा ने इसे अनुचित बताया है। भाजपा विधायकों की एक टीम ने कहा कि वे राज्यपाल के पास जायेंगे तथा स्पीकर के मनमाने तथा एवं निरंकुश निर्णय की शिकायत करेंगे।

कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात यह है कि ''हनी-ट्रैपिंग'' के राजनैतिक हथियार के रूप में उपयोग किए जाने से सदन बहुत उत्तेजित हो गया है तथा यह बहस विधानसभा से बाहर आम जनता के बीच पहुँच गई है तथा आम चर्चा का विषय बन गई है।

रोचक बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेता यह कह रहे हैं कि एक अति महत्वाकांक्षी कांग्रेस नेता, जो राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हनी ट्रैप की घटनाओं की जड़ में हैं, तथा उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की माँग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

जहाँ गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सहकारिता मंत्री द्वारा की गई शिकायत की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिये हैं, वहीं, मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने कहा है कि दोषी पाये गये किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

इसे संयोग ही कहा जायेगा कि भाजपा विधायक, सुनील कुमार, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेटे के हत्यारे माता-पिता व तीन भाईयों को आजीवन कारावास

जयपुर, 21 मार्च। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर, द्वितीय ने संपत्ति विवाद में हुए झगडे में बेटे की हत्या करने वाले पिता नवाब खां, मां जैतुन उर्फ अलमदी सहित मृतक के तीन भाइयों अमजद, सद्दाम और असफाक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने अभियुक्तों पर कुल 2.81 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

- 19 अक्टूबर 2022 के इस मामले में नवाब खां व उसकी पत्नी जैतून ने अपने तीन अन्य बेटों, अमजद, सद्दाम और असफाक के साथ मिलकर अपने ही एक और बेटे समीर को पीट-पीट कर मार डाला था, अदालत ने आरोपियों पर 2.81 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वर्तमान परिस्थितियों में ''मैरिट'' को चयन का आधार बनाना ही बेमायने है'

राहुल गांधी ने ''कास्ट सैंसस'' (जातिगत जनगणना) के पक्ष में नया तर्क दिया

- यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा, दलित, आदिवासी, ओबीसी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, शिक्षा की मुख्यधारा में, ''सोशल पोज़ीशन'' को क्षमता के रूप में आंका जाता है।
- दलित, ओबीसी व आदिवासी, अन्य ''कम्युनिटीज़'' से ''कल्चरली'' जुड़ ही नहीं पाते। अतः ''मैरिट'' का पूरा सोच एक सवर्ण (अपर कास्ट) की कहानी है।
- इसलिये केवल चुनाव जीता हुआ जनप्रतिनिधि कोई मायने नहीं रखता, जब तक, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट वर्ल्ड, इन्टैलिज़ैंस एजेन्सियों में, जो कि वाकई में पावर को कंट्रोल करती हैं, ओबीसी, दलित व आदिवासी जनता का कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये बराबरी का स्थान नहीं पा सकतीं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता के विषय में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) तथा यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन (यूजीसी) के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट के साथ चर्चा की।

गांधी ने कहा कि देश में गुणवत्ता की अवधारणा ''पूरी तरह से दोषपूर्ण'' है, क्योंकि पिछड़े समुदाय इससे जुड़े हुये नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''एक और बड़ी समस्या यह है कि दलितों का इतिहास, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास विलुप्त कर दिया गया है। मैंने कोई दलित आख्यान कभी नहीं सुना, और इसके साथ ही, आरएसएस तथा भाजपा जिस विचार को आगे बढ़ा रही हैं, वो मूलरुप से उनके इतिहास, दलितों, आदिवासियों तथा ओबीसी के इतिहास को नष्ट करने के लिए है।'' वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछड़े समुदायों का इतिहास मुख्य शिक्षा -व्यवस्था के माध्यम से जानबूझ कर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उन्होंने कहा, ''वह इतिहास मुख्य शिक्षा तंत्र के जरिये उपलब्ध नहीं है। नई दिल्ली में स्कूल जाने वाले ऊँची जाति के किसी बालक या बालिका को उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तभी तो वे ऐसी बातें कह देते हैं कि ''मुझे तो कोई जातिगत भेदभाव दिखाई नहीं देता। जाहिर है, आप जातिगत भेदभाव देखते ही नहीं हैं।'' कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह देश के पिछड़े समुदायों के साथ ''ट्रिक'' से काम ले रही है। उन्हें अपने समुदायों, जिनके पास असली सत्ता है ही नहीं, का प्रतिनिधित्व करने के अवसर दिये जाते हैं, असली सत्ता तो संस्थागत ढ़ाँचे में निहित है।

राहुल गांधी ने कहा, ''देखिये, वे (भाजपा) क्या कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो गया है कि उन्हें नीची जातियों को रास्ता देना जरुरी है। इसलिये उन्होंने नीची जतियों को प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीति का रास्ता दे दिया है, और कह दिया है कि जो भी विधायक या सांसद बनना चाहता है, बन सकता है। अर्थात, हम उन्हें बनायेंगे, भाजपा उन्हें बनायेगी। और फिर उन्होंने क्या किया कि प्रतिनिधित्व -व्यवस्था के अधिकार छीन लिए , अब ताकत या सत्ता कहाँ है? अब ताकत या सत्ता रिप्रज़ेन्टेटिव फ्रेमवर्क के बजाय, इन्स्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में समाहित कर दी गई है। ताकत अफसरशाही के पास है, ताकत कॉर्पोरेट इंडिया के पास है, ताकत गुप्तचर एजेंसियों के पास है। वे इस ''ट्रिक'' से काम ले रहे हैं कि भैया, हम आपको रिप्रज़ेन्टेशन देंगे। और रिप्रज़ेन्टेशन का मतलब कुछ नहीं। मुझे तो यही चलता दिखाई दे रहा है।'' गांधी ने कहा कि भारत में भेदभाव की सच्चाई हर व्यक्ति को ज्ञात होनी चाहिये।

महाराष्ट्र सरकार आगरा में शिवाजी का स्मारक बनाएगी

मुंबई, 21 मार्च। छावा फिल्म के बाद औरंगजेब को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। नागपुर में हिंसा के बाद यह मामला अब देश भर में चर्चा के केंद्र में है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ये इच्छा जाहिर कर चुके थे, जिसपर

- महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि आगरा में, जहाँ शिवाजी महाराज को बंदी बनाया गया था, वहाँ उनका भव्य स्मारक बनाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा शासनादेश (जीआर) जारी किया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प ने अमेरिका का शिक्षा विभाग (एजुकेशन डिपार्टमेंट) बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये

क्या अमेरिका विश्व में उच्चशिक्षा का सर्वोत्तम विकल्प होने का ओहदा खो देने की तैयारी में है

- शिक्षा विभाग बंद हो जाने से उच्च शिक्षा के लिये मिलने वाली छात्र वृत्तियां बंद हो सकती हैं, तथा राजनीतिक अस्थिरता भी एक मुद्दा बन जायेगा, विदेश से अमेरिका पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिये।
- कैनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड व जर्मनी, जहां पढ़ाई अब उतनी मंहगी नहीं लगेगी, क्योंकि बिना स्कॉलरशिप के अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन काम हो जायेगा।
- शिक्षाविदों के अनुसार, अमेरिकी युनिवर्सिटीज़ के कैम्पस भी अब राजनीति की दृष्टि से अस्थिर होंगे। क्योंकि, छात्र वृत्ति आदि के मुद्दों पर, असमानता पनपेगी, तथा कैम्पस अशान्त हो जायेंगे और सीरियस विदेशी विद्यार्थी उन विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे जहां निर्विघ्न तरीके से, बिना भारी खर्चे के पढ़ाई हो सकेगी।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शिक्षा विभाग को खत्म करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम अमेरिका शैक्षणिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा। यह विवादास्पद निर्णय, जो लम्बे समय से प्रिय कंजरवेटिव लक्ष्य को पूरा करता है, ने स्कूलों में फैडरल निगरानी के भविष्य पर बहस छेड़ दी है। जहां ट्रंप का कहना है कि यह विभाग बेकार है और सैद्धांतिक रुप से इसमें काफी समझौते किए गए हैं पर इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरुरत होगी, इस वजह से यह कर पाना मुश्किल होगा।

प्रशासन पहले ही यहां छंटनी शुरु कर दी है और कई ऑफिसो से अधिकारियों को हटा कर उन्हें बंद कर दिया है। अरबों डॉलर्स की फैडरल एजुकेशन फंडिंग और स्टूडैंट्स लोन अधर में लटक गए हैं। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह इस भारी बदलाव से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थी पिछड़ जाएंगे। विभिन्न संगठनों, जिनमें नैशनल पेटेंट्स यूनियन भी शामिल है, ने इसका विरोध करने की बात कही है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को भंग करने से शिक्षा सुधार नहीं होगा बल्कि इससे लाखों विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

रिपब्लिकन पार्टी के भी इसे लेकर संदेह पैदा हो गया है। कांग्रेस कुछ सदस्य इस फैसले की व्यवहार्यता राजनैतिक परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन ट्रंप अपने निर्णय पर अड़िग हैं वे शिक्षा विभाग को कट्टर पंथियों और नौकरशाही की दखलंदाजी का गढ बता रहे हैं। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी हैं और अमेरिकन शिक्षा का भविष्य खतरे में आ गया है। ट्रंप का स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण निर्णय लागू होगा या फिर इसे कांग्रेस, शिक्षाविदों और अभिभावकों का विरोध सहना होगा। पर एक बात तो तय है कि यह लड़ाई लम्बी चलने वाली है।

अमेरिका की सीमाओं के पार भी फैडरल फंडिंग, शिक्षा ऋण पर अनिश्चितता कायम है और सिविलराइट्स संरक्षण की समस्याओं के कारण अन्य देशों के छात्र अमेरिका में पढ़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे है। अमेरिकन युनिवर्सिटीज़ में भारी उथल-पुथल की संभावना है, इसलिए विद्यार्थियों में अन्य विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कैनडा जैसे देश अपनी स्थिर नीतियों व उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था के कारण छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दुनियाभर के छात्रों में लोकप्रिय है और अब तो उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। यू.के. जहां विश्व की प्रतिष्ठित युनिवर्सिटीज़ हैं वहां भी नए विद्यार्थियों के आने की संभावना काफी ज्यादा हैं। जर्मनी अपनी कम फीस और बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण लोकप्रिय हो रहा है।

इससे स्पष्ट है कि इन परिवर्तनों से उच्चशिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा है। अगर शिक्षा विभाग खत्म हो जाता है और संघीय निगरानी में कमी आती है तो शैक्षणिक क्षेत्र में अमेरिका का नेतृत्व घट सकता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभाए अन्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सौरभ भारद्वाज दिल्ली में आप के अध्यक्ष नियुक्त

नयी दिल्ली, 21 मार्च। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के नए प्रभारी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन सह प्रभारी बनाए गए हैं।

शुक्रवार को 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई पार्टी की

- आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व उद्योग मंत्री सत्येन्द्र जैन को पंजाब में आप का प्रभारी नियुक्त किया है।

पीएसी बैठक में सिसोदिया को पंजाब प्रभारी बनाने का निर्णय हुआ। नए फेरबदल के तहत 'आप' ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)